

भारत में रह रहे यहूदी जनजाति की होगी ‘घर वापसी’

● सदियों से रहने वाले यहूदियों को वापस ले जाएगा इजरायल

तेल अवीव/नई दिल्ली (एजेंसी)। इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने उस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत में रहने वाले यहूदी जनजातियों को वापस ले जाना है। रविवार को इस फैसले को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत इजरायल ने 2030 तक बेनी मेनाश समुदाय के करीब 5,800 सदस्यों को शामिल करने के प्लान को मंजूरी दे दी है। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों मिजोरम और मणिपुर में रहने वाले ये यहूदी



नेतन्याहू सरकार ने दी मंजूरी, जनसंख्या बढ़ाना है बड़ा लक्ष्य

समुदाय के लोग सदियों से भारत में रह रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार ने इन्हें धीरे-धीरे उत्तरी इजरायल के गैलिली इलाके में बसाने को मंजूरी दी है। हालांकि ये क्षेत्र काफी संवेदनशील है और यह इलाका, लेबनान के हिज्बुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप के साथ लड़ाई से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। पिछले दो सालों से चल रही लड़ाई में इस इलाके में रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को जरूरी और जायोजी बनाया और कहा कि इससे इजरायल का उत्तरी इलाका मजबूत होगा। पहला समूह 1,200 लोगों का होगा।

आईएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई न हुई तो आंदोलन का अगला चरण, ज्ञापन सौंपा

भोपाल। अजाक्स संगठन के प्रांतीय अधिवेशन में नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष और विवादित आईएसएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा सवर्ण समाज की बेटियों के बारे में अत्यंत आपत्तिजनक निर्दनीय असंसदीय बयान के विरोध में आंदोलन के प्रथम चरण में उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और सचिव (कार्मिक) एम सेल्वेनद्रन को सुधीर नायक अध्यक्ष मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। मंत्रालय संघ के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी नेता अनिल तिवारी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर मंत्रालय संगठन के पदाधिकारी आशीष सोनी, दयानंद उपाध्याय, सतीश शर्मा, श्याम बिहारी दुबे सपाक्स के सचिव अमरेश गालर उपस्थित थे। बड़ी संख्या में मंत्रालय के सामान्य वर्ग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। महिला कर्मचारियों की उपस्थिति बड़ी संख्या में थी। उपमुख्यमंत्री ने अपने चैंबर से बाहर आकर ज्ञापन लिया और न्यायोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। तत्पश्चात सचिव कार्मिक श्री एम सेल्वेनद्रन जी को भी ज्ञापन देकर श्री संतोष वर्मा जी के विरुद्ध आईएसएस आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की मांग की गयी। इस अवसर पर लिपिक संघ की ओर से श्री एम एल शर्मा, श्री संतोष दीक्षित, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की ओर से विजय रघुवंशी उमाशंकर तिवारी कर्मचारी मंच की ओर से अशोक पाण्डे जी भी उपस्थित रहे और अपने संगठनों की ओर से भी समर्थन जताया। युवा ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष रामनारायण अवस्थी की ओर से भी उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। नायक ने चेतावनी दी कि यदि दो तीन दिन के भीतर संतोष वर्मा के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो आंदोलन के अगले चरण घोषित किए जायेंगे।



गुणवत्ता का नहीं मिला सड़क निर्माण, हटाने के दिए निर्देश

मुख्य अभियंता ने किया औचक निरीक्षण

भोपाल। सड़क निर्माण में गुणवत्ता का अभाव मिलने पर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता ने निम्न स्तर के कार्य को हटाने एवं सील कोट को दोबारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य अभियंता विजय कुमार गुप्ता विगत दिवस गुना जिले के बामोरी में 2 करोड़ 98 लाख की लागत से बन रही सड़क का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। एबी रोड - आगरा रोड पर पिपरोदा हसली तक की इस सड़क के निरीक्षण में मुख्य अभियंता ने पाया कि सड़क के कुछ हिस्से में बोटी कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं है और सड़क के कुछ हिस्सों में सील कोट भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने तत्काल महाप्रबंधक को बोटी के घटिया कार्य को हटाने और जहाँ आवश्यक हो, सील कोट को दोबारा करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता का निर्देश मिलते ही विभागीय अधिकारियों ने निम्न स्तर के निर्माण कार्य को निर्माण एजेंसी से हटवाया। उक्त सड़क की लंबाई 4.8 किमी है। मुख्य अभियंता के औचक निरीक्षण के दौरान सोहन ग्रेवाल महाप्रबंधक एवं ओ पी दसौरा मुख्य महाप्रबंधक सहित एक्स्कुसी के टीम लीडर, प्रभारी सहायक प्रबंधक उपस्थित थे।

मानव समाज की रचना का एकात्म दर्शन भारतीय जीवन शैली के सोच के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पं दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर उद्बोधन

नई दिल्ली। भारतीय संस्कृति के सच्चे अग्रदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का समग्र चिंतन भौतिकता की मायावी चमक के विपरीत वैश्विक कल्याण की विशुद्ध भारतीय परिकल्पना के सनातन प्रवाह का अमृत कलश है जिसकी आराधना का केंद्र समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ वह अंत्यज है जिसका समग्र उत्थान अपेक्षित है। यह कल्पना नहीं, वरन यूरोपीय पुनर्जागरण के अधूरे अपुष्ट मानववाद से भिन्न वर्ग संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की खाँड़ित दृष्टि को चुनौती देता हुआ भारतीय जीवन शैली के अनुरूप प्रगतिशील मानव समाज की रचना का एकात्म दर्शन है।

ये उद्गार डॉ. अशोक कुमार भागव पूर्व कमिश्नर रीवा एवं शहडोल संभाग ने विश्व हिंदी परिषद एवं भारतीय दार्शनिक के अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में विज्ञान भवन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ‘पं दीनदयाल उपाध्याय : प्रकृति, संस्कृति और दर्शन’ विषय पर विशिष्ट वक्ता के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पंडित जी ने सिद्धांत की बलि चढ़ाकर मिलने वाली विजय को पराजय से भी ज्यादा बुरा मान और वे ऐसी विजय के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने राजनीति में सदैव वैचारिक निष्ठा और आचरण की शुचिता को महत्ता दी। भारत ही वह महान सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती हुई एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। इसलिए कि जब युगों का इतिहास लिखा जाए, तो उसमें यह अंकित हो कि जब शासन प्रशासन अथवा राजसत्ता का प्रमुख पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है तभी रामराज की परिकल्पना साकार होती है। क्योंकि, कोई



भी व्यवस्था मनुष्य के कुशल क्षेम के बिना सफल नहीं हो सकती। पंडित जी राष्ट्र निर्माण के मंदिर में महर्षि दधीचि की भाँति अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीतरागी साधक थे जो सत्ता के साकेत से दूर रहकर राष्ट्रीय चिंतन में विचारों की एकता, तथ्यों की एकता और मूल्यों की एकता पर बल देते थे। उनके लिए राष्ट्रवत्ता का आधार भारत माता है केवल भारत नहीं। यदि माता शब्द हटा दींजिए तो भारत भूमि का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा। डॉ. भागव ने कहा कि आज समग्र संसार युद्ध की विभीषिका, भय, असुरक्षा आतंक और प्राकृतिक प्रकोपों के घोर नैराश्य के अंधकार में डूबा हुआ है।ऐसी विषम स्थिति में पंडित जी का मानव केंद्रित मानव उत्कर्ष को समर्पित एकात्म दर्शन कल भी प्रासंगिक था आज भी प्रासंगिक है।

इस अवसर पर डॉ. अशोक कुमार भागव को पं दीनदयाल

उपाध्याय पर उनके उत्कृष्ट आलेख के लिए संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य इथियोपिया दूतावास के गेब्रे टेकेले विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. विपिन कुमार और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के संयोजक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो रामनारायण पटेल ने सम्मानित किया। इस सम्मेलन में मुख्य अथागत लद्दाख के उपराज्यपाल कबींद्र गुप्ता, केसी त्यागी, पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ नेता रेखा शर्मा, राज्य सभा सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, सूरीनाम और इथियोपिया दूतावास प्रतिभागी सहित देश के अन्य विद्वतजन तथा शोधार्थी छात्र एवं श्रीमती आशा भागव आदि सम्मिलित थे।

उह जोन कैंकटीम कई राज्यों के नेताओं की ड्यूटी

बीजेपी का बंगाल प्लान तैयार,2026 फतह की तैयारी

कोलकाता (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजे आने के साथ ही अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में मैजिक नंबर 148 है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 38 फीसदी वोट के साथ 77 सीटें जीती थीं। पांच साल पहले बीजेपी ने सीटों की संख्या और वोट प्रतिशत में



लंबी छलांग लगाई थी मगर टीएमसी से काफी पीछे रह गई थी। तुणमूल कांग्रेस 48 फीसदी

वोट प्रतिशत के साथ 215 सीटें हासिल कर जीत की हैट्टिक लगा दी थी।

पहाड़ साधेंगे प्रदीप,राढ़बंग में छत्तीसगढ़ी नेता को जिम्मा

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर पश्चिम बंगाल को 6 चुनावी जोन में बांटा है। दार्जिलिंग और पहाड़ी क्षेत्र की जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को सौंपी गई है। उनके साथ पूर्व आईपीएस पंकज कुमार सिंह को रखा गया है। पंकज कुमार सिंह गोरखा नेताओं के साथ अदम्य गोरखालैंड के लिए बातचीत में मध्यस्थ भी रहे हैं। यह टीम दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और कुचबिहार में काम करेगी। राढ़बंग बेल्ट यानी पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, पुरबा और पश्चिम बर्धमान, आसनसोल में छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश महामंत्री पवन कुमार साई और उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की ड्यूटी लगाई गई है। यह टीम आसनसोल-बर्नपुर-दुर्गापुर जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट में हिंदी भाषी वोटरों पर फोकस करेगी।

टीएमसी के गढ़ में हिमाचल-हरियाणा के नेता

हावड़ा-हुगली-मेदिनीपुर इलाका हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रदेश महामंत्री पवन राणा और हरियाणा के पूर्व सांसद संजय भाटिया को सौंपी गई है। यह इलाका टीएमसी का गढ़ रहा है। इन नेताओं के सामने बीजेपी की हारी सीटों पर जीत के लिए माहौल और प्लानिंग की चुनौती है। शहरी इलाके कोलकाता मेट्रोपॉलिटन और दक्षिण 24 परगना के प्रभारी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महामंत्री रहे एम. सिद्धार्थन हैं। उनके साथ कर्नाटक के बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि को तैनात किया गया है। बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों की तरह बंगाल में भी शहरी वोटरों को हासिल करना चाहती है, जहां टीएमसी के ट्रेडिशनल वोटर हैं।

350वां शहीदी दिवस पर पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर को नमन कर नवाया शीश

हरियाणा(एजेंसी)। हरियाणा कुरुक्षेत्र में ‘हिंद की चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मना रही है। इस मौके पर एक बड़ा समागम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 350वें शहीदी दिवस के मौके पर हरियाणा पहुंचे। इस दौरान पीएमनरेंद्र मोदी ने हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए शीश नवाया। मुगल आक्रांताओं को लेकर पीएम मोदी ने कहा हम सब जानते हैं कि मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ भी वरुरता की सारी हदें पार कर दी थीं। वीर साहिबजादे दीवार में जीवित चिनवाए जाने को तैयार हो गए, लेकिन अपने कर्तव्य और धर्म को नहीं छोड़ा।

4300 किमी दूर दिल्ली पहुंचा इथोपिया की राख का ‘गुबार’

● 12 हजार साल बाद फटा ज्वालामुखी, 15 किमी ऊंचा उठा

अदीस अबाबा (एजेंसी)। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12 हजार साल बाद अचानक रविवार को फटा गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और स्ल्फर डाईऑक्साइड करीब 15 किमी ऊंचाई तक पहुंच गई। यह लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। सोमवार रात करीब 11 बजे यह राख इथियोपिया से 4300 किमी दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर और पंजाब तक फैल गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राख के बादल मॉलवार शाम 7.30 बजे तक भारत से साफ हो गए और चीन की ओर बढ़ गए हैं। इस गुबार की वजह से एफए इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी थीं। एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस गुबार की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी कम हुआ।



हिन्दी की रचनात्मकता पर केन्द्रित विस्तृत रिपोर्ट ‘विश्व में हिन्दी’ तथा ‘विश्व रंग परिवार की पत्रिकाओं’ इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए’, ‘रंग संवाद’, ‘वनमाली कथा’ और ‘विश्व रंग संवाद’ के विशेषकों के साथ ही आईसेक्ट प्रकाशन की अन्य पुस्तकों की वृहद श्रृंखला होगी।

जनजातीय प्रकोष्ठ ‘आदिरंग’ – विश्व रंग का एक और विशेष प्रकोष्ठ है ‘आदिरंग’। रवीन्द्र भवन में टंटया भील सभागार आदिरंग की गतिविधियों का केन्द्र होगा। यहाँ जनजातीय साहित्य, संस्कृति, कला और पारंपरिक शिल्प कला कोशल पर एकाग्र वैचारिक सत्रों के साथ ही विश्व रंग फाउण्डेशन द्वारा निर्मित दो हेरिटेज फ़िल्मों ‘गणगौर गाथा’ तथा ‘संजा’ के प्रदर्शन भी होंगे। इस प्रकोष्ठ में जनजातीय विरासत पर केन्द्रित शिल्पों और चित्रों की दीर्घा भी आकर्षण का केन्द्र होगी। ‘कठपुतली’ कला की जनसंचार उपयोगिता पर प्रस्तुति-सह-प्रदर्शन भी होगा। साथ ही पारंपरिक व्यंजनों की सौगात भी होगी।

समापन समारोह में पुरस्कृत होंगे विश्व हिन्दी ओलंपियाड के विजेता – विश्व रंग का औपचारिक समापन 29 नवंबर की शाम 6 बजे रवीन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में होगा। इस अवसर पर मॉरिशस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन के मुख्य आतिथ्य, पूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियात निशंक की अध्यक्षता, म.प्र. के उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल तथा आरएनटीयू के कुलाधिपति संतोष चौबे की विशेष उपस्थिति में विश्व हिन्दी ओलंपियाड के विजेताओं की घोषणा कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। म.प्र. के अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला, विश्व रंग के सह निदेशक डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी और निदेशक बालरंग डॉ. पल्लवी राव चतुर्वेदी का भी प्रेरक सानिध्य रहेगा।

संविधान दिवस पर विशेष	
 सुनील कुमार गुप्ता	
 लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।	

संविधान एक दृष्टिकोण है, एक रोशनी है, जो हमें, देश को आगे बढ़ा सकता है। संविधान के दस्तावेज में हर शब्द नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन उसके भाव और नैतिकता महत्वपूर्ण है, जिसे अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। - मदन बी. लोकरुर, सेवानिवृत्त जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट

आज 26 नवंबर है, जो ऐतिहासिक दिन जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यह वह दिन है, जब सन् 1949 को देश का अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था । 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया। भारत के संविधान को दुनिया को अनुा संविधान भी माना जा सकता है। दरअसल यह केवल व्यक्ति के अस्तित्व, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गरिमा का ही ध्यान नहीं रखता है, बल्कि पूरे विश्व, महाद्वीप और प्रकृति के संरक्षण और मानवता की बात भी करता है।

हम जब देश के संविधान बनने के सफरनामे, उसकी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि पाते हैं, कि यह केवल एक कानूनी, अनुच्छेदों से भरा एक दस्तावेज मात्र नहीं हैं, बल्कि इसमें शामिल हर पंक्ति के पीछे सामाजिक, आर्थिक बदलाव, सुधार के ठोस तर्क मौजूद हैं। संविधान बनाने वालों ने भारतीय समाज की बुराईयाँ और विसंगतियों को छिपाने की कोशिश नहीं की। भारत के लोग जिन बुनियादी अधिकारों से वंचित थे, उनका पूरा संरक्षण करने वाली व्यवस्था बनाने की पहल इस संविधान में की गई।

भारतीय संविधान की विकास यात्रा, तथ्य और तर्कों पर लिखी पुस्तकों का अध्ययन करने पर पाते हैं कि भारत का संविधान कोई एक बार की पहल में लिखा गया संविधान नहीं है, इसके पीछे सवा सौ सालों के सामाजिक सुधार के अभियानों, ब्रिटिश सरकार द्वारा डेढ़ सौ सालों में बनाए गए अलग-अलग कानूनों के अनुभव और न्यायिक स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के द्वारा 50 सालों में बनाए गए अलग-अलग प्रारूप खड़े हुए हैं ।

हमारे संविधान को बनाने में उन्नीसवीं सदी की शुरुआत से हुए सामाजिक सुधार आंदोलन मील का पथ्रर साबित हुए। इन पहलों ने भारतीय समाज में यह चेतना जागृत करना शुरू की कि भारत में ऐसी संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, जो आपसी

संविधान दिवस विशेष
 चित्रा माली
 सहायक प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महत्वा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विधि क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता।

1930 के शुरुआती दशक से ही कांग्रेस ने इस बात को ज़ोर दिया था कि भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। 1946 में लॉर्ड वेवेल ने इस बात पर सहमति जतायी और प्रांतीय चुनावों के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। इनके अतिरिक्त सभा में रजवाड़ों के सुन्दाय भी शामिल थे क्योंकि एक-एक कर रजवाड़ें भारतीय संघ में शामिल होते जा रहे थे। एक राष्ट्रवादी अखबार ने लिखा कि गांधी टोपी और नेहरू जैकेटों से भरी सभा में ‘नौ महिला सदस्य भी मौजूद थीं,जो संविधान सभा को सतरींगी बना रही थीं’। संविधान सभा के सभी सदस्यों में वैचारिक भिन्नता समाहित थी। कुछ सदस्य नास्तिक,कुछ आध्यात्मिक, कुछ धर्मनिरपेक्ष, कुछ समाजवादी,तो कुछ जमींदार वर्ग के समर्थक थे। आम जनजीवन से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा विचार होगा जिसकी नुमाइंदगी संविधान सभा में न की गई हो। संविधान सभा की प्रक्रिया को जनापेक्षी बनाने के लिए जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। सैकड़ों तरह के सुझाव व मांग समिति के पास पहुंचे थे। इनमें से कुछ एक अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज संघ (कलकत्ता की संस्था) ने सुझाव दिया कि ‘भारत का संविधान प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए’। गौहत्या पर प्रतिबंध और बुचड़खानों को बंद करने संबंधी मांग स्वरूप सुझाव। निचली जातियों के समूहों ने ‘उनकी जातियों द्वारा उनके प्रति किए जा रहे भेदभाव को खत्म करने की मांग की और विधायिकाओं,सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों में अपने लिए आरक्षण की मांग की’। भाषायी अल्पसंख्यकों ने मांग की कि ‘उनकी मातृभाषा में उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए और भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए’। धार्मिक अल्पसंख्यकों के समूहों ने उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। विशाखापटनम के जिला शिक्षक संगठन और बंबई के केंद्रीय यहूदी बोर्ड ने भी अपने लिए विधायिका समेत सभी सरकारी संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व की मांग

संविधान दिवस विशेष
 प्रमोद दीक्षित मलय
 लेखक शैक्षिक संवाद मंच उ.उ. के संस्थापक हैं।

परिवार देश की लघुतम इकाई होती है। परिवार से मिलकर ही एक वृहत् समाज की रचना सम्भव होती है। प्रत्येक घर-परिवार एवं समाज में सदस्यों के कार्य व्यवहार एवं आचरण हेतु एक अलिखित नियमवली या सहिता होती है। परिवार एवं समाज अपने सदस्यों से अपेक्षा रखता है कि समाज की बेहतरी के लिए सभी जन इन नियमों का पालन करते हुए तालमेल एवं संगति से ही कार्य संपादन करेंगे। नियमानुकूल आचरण कर समाज की विकास धारा को गतिशील रखते हुए उसे समृद्धि प्रदान करेंगे। नियमों में आबद्ध लोक अपनी कार्य संस्कृति से सतत ऊर्ध्वगामी यात्रा करता है। नियमानुशासित लोकाचरण से समाज में सद्बुति, सद्दनीति, शुचिता, सत्यान्वेषण, सहकार, समन्वय, संरक्षभाव एवं सदस्यकारों का बीजवपन, पल्लवन एवं फलन होता है और अराजकता, अनीतिकता, अशौच, अनीति के लिए कोई स्थान शेष नहीं होता। इन नियमों के परिनिष्ठित, परिमार्जित, प्रांजल लिखित स्वरूप को देश के संदर्भ में संविधान संज्ञा से अभिहित किया जाता है जिसमें लोक की शक्ति निहित होती है और जो विधायिका से अनुमोदित होता है। हम कह सकते हैं कि संविधान

वीथिका

संविधान में लिखे शब्द नहीं, उसके भाव और नैतिकता महत्वपूर्ण

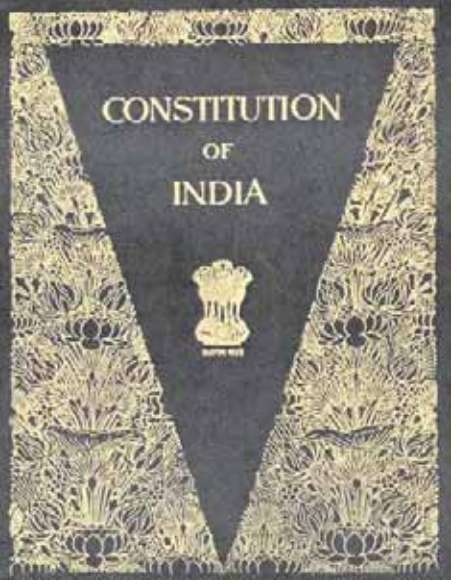
हमें एक अच्छा संविधान मिला है, पर यह हमारे नेताओं पर निर्भर करता है कि वो कैसे संविधान को आगे बढ़ाएं। वो अच्छे संविधान को बुरा बना सकते हैं और एक बुरे संविधान को भी अच्छा बना सकते हैं. : डॉ. भीमराव अंबेडकर

प्रेम को बढ़ावा दे और शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करे और न्याय की अवधारणा को स्थापित करे। इसमें सेरामपुर मिशन प्रेस के माध्यम से सन् 1800 में बंगाल में जन शिक्षण को बढ़ावा देने की पहल, 1828 मे राजा राममोहन राय द्वारा की गई सती प्रथा और बाल विवाह की कुुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज सुधार की पहल, 1848 में सावित्री बाई फुले द्वारा महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने और 1853 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोलने की पहल, 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा समाज में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई सत्य शोधक समाज की स्थापना, महिलाओं को शोषण से मुक्त कराने की पहल को हम सब जानते हैं। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिशों से हिन्दू पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना। वर्ष 1882 में रमाबाई के आर्य महिला समाज संगठन के माध्यम अनाथ संरक्षण और बालिका शिक्षा के कार्यों को कौन भुला सकता है। सर सैय्यद अहमद खान ने 1863 में मुस्लिम समुदाय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए साइंटिफिक सोसायटी की स्थापना की। 1875 में हिन्दु समाज सुधार की पहलों के लिए चिरपरिचित गुजरात के स्वामी दयानंद सरस्वती, 1905 में शिक्षा, स्वास्थ्य, शराबबंदी, गरीबी, छुआछूत और अस्पृश्यता, सामाजिक विसंगति के खिलाफ अपनी संस्था के माध्यम से पहल करने वाले बाल कृष्ण गोखले, केंरल के श्री नारायण गुरु, आंध्र प्रदेश के कंदुकूर वीरेश लिंगम,, डॉ. आत्मारंग पांडुरंग, स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर ही देश की भीतरी विसंगतियों को दूर करने करने के लिए जी-जान से जुटे रहे महात्मा गांधी जैसे पुरखों के विचार-कर्मपथ और भाव दर्शन हमारे संविधान में आपको मिल जाएंगे।

राजनैतिक पहलों का इतिहास भी आप तलाशेंगे तो पाएंगे इसकी शुरुआत 1895 से हो गई थी। व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक संगठनों से लेकर उस दौर की रियासतों, राजे-रजवाड़ों तक ने आजादी के बाद देश की व्यवस्था, नियम-कानूनों कैसे होंगे, इसके अपने-अपने प्रारूप बनाए थे और संविधान सभा तक पहुंचे थे।

देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन

उससे पहले से संविधान सभा के 299 सदस्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने में लगे हुए थे। यह काम इतना आसान नहीं था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 2 साल 11 महीने, 18 दिनों तक कई बैठकों और बहसों के लंबे दौर चले। इसके बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसे अंतिम रूप दिया। 26



नवंबर 1949 साधारण सभा की आखिरी बैठक में इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्षित किया गया। इसीलिए हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह विश्व का सबसे बड़ा और हस्तलिखित संविधान है। जब संविधान बना, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। समय-समय पर हुए संशोधनों के बाद वर्तमान में संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों की श्रेष्ठ अवधारणाओं और संवैधानिक मूल्यों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल

भारतीय संविधान की उद्देशिका एक संकल्प है

की। वैचारिक विभिन्नता और मांगों की विविधता के बीच भारत के संविधान को सामंजस्य स्थापित करना था। भारतीय संविधान संभवतः विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण दिसंबर 1946 से लेकर 1949 तक किया गया (जिसमें दो वर्ष ग्यारह महीने और 17 दिन का समय लगा) और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। संविधान निर्माण के समय संविधान 22 भागों में विभाजित था और उसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान वर्तमान में 25 भागों में विभाजित है और उसमें 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की बैठक 11 सत्रों में आयोजित की गई और 165 दिन इस पर बहस की गई थी। भारतीय संविधान सभा की संपूर्ण कार्यवाही को ग्यारह अंकों में प्रकाशित किया गया है। इनमें से कई अंक तो 1000 पृष्ठों से भी अधिक के हैं। संविधान सभा में 300 से भी अधिक सदस्य थे जिनमें से 20 सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे इनमें से बारह के पास विधि की डिग्री थी जिनमें कांग्रेस के मुख्य नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारत के महान और गौरवशाली अतीत और गांधी जी की भावनाओं के साथ-साथ फ्रांस,अमेरिका और रूस की क्रांति के आधुनिक दृष्टांतों का उल्लेख भी किया।

अनेक महत्वपूर्ण भाषण में उन्होंने कहा था कि ‘भारत को स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य घोषित किया गया है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक न्याय में अवसर की समानता,विधि की समानता, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार,आस्था,पूजा, रोजगार, संगठन और सक्रियता की स्वतंत्रता (कानून और जन-नैतिकता के दायरे में) प्रदान की गई हैं’। इसके अलावा अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी इलाकों, वंचितों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की उचित देखभाल करने की बात भी कही। कांग्रेस के दूसरे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न समितियों की कार्यवाहियों में गहन रूप से हिस्सा लिया और उन्होंने कई

रिपोर्ट्स भी तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में यह पटेल ही थे जिन्होंने परस्पर विरोधी विचार वाले सदस्यों के बीच मध्यस्थता का काम किया और कई मुद्दों पर आम सहमति कायम की। हठी और जिद्दी किस्म के सदस्यों से पटेल सुबह टहलते समय बात करते थे और उन्हें मुद्दे पर व्यापक दृष्टिकोण से अवगत कराते थे। अल्पसंख्यकों का अधिकार संबंधी प्रस्ताव संविधान सभा में सरदार पटेल के द्वारा ही पेश किया गया था। संविधान सभा के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के उद्घाटन के दिन ही इन्हें नामांकित किया



गया था और वे अपने कार्यालय की समाप्ति तक इस पद पर गरिमापूर्ण तरीके से विराजमान रहे। आपका कार्य बड़ा जटिल था आपको बहस और विवाद करते समूहों के बीच शांति स्थापित करना था इसी के साथ उन्हें समय-सीमा का ध्यान रखने वाले अधिकारी को भी निर्देशित करना होता था और सभी वक्ताओं को धैर्य से सुनना भी पड़ता था। क्योंकि आमतौर पर भारतीय लोग श्रोता की तुलना में वक्ता ही बेहतर होते हैं खासतौर पर भारतीय राजनेताओं के साथ ऐसा ही होता है। कांग्रेस की इस त्रिमूर्ति से अलग संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के

किया गया है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि जो लोग भारत का संविधान बना रहे थे, वे आपस में भी एकमत नहीं थे। उनके विचारों में भारी टकराव था, इसके बावजूद वे हिंसक नहीं थे। उनका विचारों की विविधता और परस्पर प्रेम के भाव में भरपूर विश्वास था। असहमतियां थीं, लेकिन कोई भी सह-अस्तित्व की अनिवार्यता से समझौता नहीं कर रहा था।

जब संविधान की रचना की जा रही थी, तब संविधान सभा में शामिल लोगों ने कई बार कहा था कि हमें एक बेहतर भविष्य के लिए संविधान बनाना है। हमें उन मूल्यों को तय करना है, जिनसे भारत के स्वभाव और चरित्र का निर्माण हो। लेकिन वह यह भी कह गए कि संविधान कितना भी अच्छा बना लीजिए, यदि इसे लागू करने वाले लोगों का समूह और उनका विचार दूषित हुआ, तो अच्छे संविधान के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। संविधान बनने के बाद संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि, हमें एक अच्छा संविधान मिला है, पर यह हमारे नेताओं पर निर्भर करता है कि वो कैसे संविधान को आगे बढ़ाएं। वो अच्छे संविधान को बुरा बना सकते हैं और एक बुरे संविधान को भी अच्छा बना सकते हैं।

अभी हाल ही संविधान संवाद की एक व्याख्यानमाला में अपने संबोधन में सुप्रीमकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस मदन बी. लोकरुर ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे संविधान में तीन चार बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो है प्रस्तावना- जिसमें मार्गदर्शक है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, ये मूल्य आधारित दृष्टिकोण हैं, जिससे हम अपने संविधान को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा-संविधान हमें कुछ बुनियादी अधिकार देता है, जैसे-जीवन जीने, अभिव्यक्ति, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता आदि। तीसरा- संविधान में हमारे कर्तव्यों का भी उल्लेख है। लेकिन वह नहीं हो सकता है कि आप प्रस्तावना को एक तरफ रखें और अधिकारों को दूसरी तरफ और अपने स्वार्थ के हिसाब से संविधान को आगे बढ़ाएं। दरअसल संविधान एक दृष्टिकोण है, एक रोशनी है, जो हमें, देश को आगे बढ़ा सकता है। यह देश के हम यानी नागरिकों और नेताओं पर निर्भर है कि वह इसका कैसे उपयोग करें और कैसे आगे बढ़ाएं। संविधान के दस्तावेज में हर शब्द नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन संवैधानिक भाव और नैतिकता महत्वपूर्ण

है, जिसे अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। यह बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज व्यवस्था की ओर से कई काम और फैसले ऐसे किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिक को न्याय नहीं मिल रहा, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का संरक्षण नहीं हो रहा है।

भारतीय संविधान विविधता और अनेकता में एकता का अनुकरणीय उदाहरण है, जो विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, जातियों, भाषाओं, पहनाओं और परंपराओं के लोगों को एक साथ परस्पर, प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ रहने का संदेश देता है। संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति ही है ‘हम, भारत के लोग’, यह वाक्यांश ही स्पष्ट कर देता है कि भारत का संविधान अपने अधिकार और वैधता लोगों से प्राप्त करता है, कहीं बाहरी व्यक्ति या शक्ति द्वारा थोपा नहीं जाता, बल्कि लोगों द्वारा स्वयं तैयार किया और अपनाया जाता है. संविधान की प्रस्तावना में कि उसे हर बच्चे पर दिया गए कि भारतीय संविधान का मूल आधार न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गरिमा जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य हैं। दरअसल मानवीय मूल्य ही संवैधानिक मूल्य है, जिसमें प्रेम, दया और करुणा को विशेष स्थान दिया गया है।

भारतीय संविधान यह तय करता है कि देश में कोई भी व्यवस्था, चाहे वह विधायिका, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका अथवा भारतीय दण्ड संहिता का अनुपालन, सभी को संविधान के दायरे में नियम-कानूनों के अनुसार ही चलेगी। संविधान से परे कुछ भी नहीं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी परिभाषित किया गया है। वंचित वर्ग, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि उसे हर बच्चे को अधिकार मिले, जो समाज के सक्षम वर्ग को प्राप्त हैं, बशर्ते सत्ता में बैठे लोग, व्यवस्था संविधान की इस भावना को समझें और शब्द नहीं, नैतिकता के आधार पर सही-गलत के फैसले करें।

संविधान दिवस हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति अपने देश के संविधान को लेकर शिक्षित हों, जागरूक हों, उसे जाने और मानें। आइए संविधान दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि संविधान के मूल्यों को जीवन में अपनाएंगे और भारत को एक सशक्त, समृद्ध और न्यायप्रिय राष्ट्र बनाएंगे।

संविधान दिवस

में रख कर की गई है। जो हर एक नागरिक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र विकास के लिए वचनबद्ध है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन इसी उद्देश्य के साथ किया गया है जिससे किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है उसके चाहे पर भी नहीं। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का समावेश भी इसमें किया गया है ताकि कल्याणकारी राज्य का सपना साकार किया जा सके। इसी के साथ नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन भी भारतीय संविधान में किया गया है। 25 जनवरी 1949 को डॉ. बी.आर.अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत के लोग भी लोकतंत्र की कुछ प्रणालियों से जरूर वाकिफ़ थे। एक ऐसा भी वक्त था जब हिंदुस्तानिक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। 1976 में बयालीसवें संविधान संशोधन के बाद समाजवाद और सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना इस प्रकार थी ‘हम भारत के लोग,भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार,अभिव्यक्ति, विश्वास,धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली

बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत,अधिनियमित और आत्मार्षित करते हैं।’ हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्षित करते हैं। तीन जनवरी 1977 में प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के स्थान पर ‘समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य’ शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक एक शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ और महत्वपूर्ण स्थान है जो भारत को एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। भारतीय संविधान की रचना अंतिम व्यक्ति को ध्यान

संविधान ही है लोक एवं देश का मार्गदर्शक

व्यष्टि से समष्टि की एक सुखाकांक्षी यात्रा है जिसमें लोक कल्याणकारी एवं समतामूलक समाज चरना के सूत्र आधार रूप में विद्यमान होते हैं। संविधान लोकमंगल, लोक सुख-समृद्धि एवं लोक चेतना का उद्घोष करता है। भारत में हम 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाकर न केवल संविधान बनाने वाले डॉ.भीमराव अम्बेडकर एवं अन्य विधि वेत्ताओं के योगदान एवं प्रयासों को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बल्कि देश में एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर बंधुत्व भाव के प्रसार के लिए भी संकल्पित हो कटिबद्ध होते हैं।

संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है जो 25 भागों में विभाजित है। समिति ने भारतीय संविधान को पूर्ण करने में 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन समय लिया और 166 दिन बैठक कर 114 दिन बहस किया था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसम्बर 1946 में हुई थी। भारत का संविधान लचीला है और कठोर भी। लचीला इस संदर्भ में कि संसद कुछ कानूनों में सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है लेकिन कुछ प्रावधानों में संशोधन हेतु राज्य सरकारों की सहमति एवं दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। संविधान में

पहला संशोधन 1951 में हुआ था और अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना न केवल संविधान का परिचयात्मक खंड है बल्कि दार्शनिक आधार भी। प्रस्तावना का आरंभ वाक्यांश ‘हम भारत के लोग’ से होता है अर्थात संविधान लोक के शक्ति का प्रतिबिंब है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी देता है। व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की अखंडता हेतु वह बंधुत्व भाव को महत्वपूर्ण मानते हुए तदनुकूल आचरण की अपेक्षा करता है। नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा गया है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्पत् 2006 विक्रमी को अंगीकृत किया गया था। इस दिन को स्मरण रखने और डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार द्वारा 2015 में डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर मुंबई में उनकी स्टैच्यू आफ इकलिट्री मेमोरियल की आधारशिला रखने के दौरान घोषणा की गई थी। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संपूर्ण देश में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर

संविधान दिवस मना कर देश भीमराव अंबेडकर को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हालांकि अंबेडकर के प्रयासों को सामान्य जनमानस तक पहुंचाना एवं देश में भाईचारे की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस हम पहले भी मनाते रहे हैं। संविधान बनाने हेतु संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में मान लिया था। 29 अगस्त, 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की समिति की स्थापना की गई थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर चुने गए थे। संविधान सभा में विभिन्न रियासतों से 389 सदस्य थे लेकिन देश विभाजन के बाद 299 सदस्य ही बचे। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा का सदस्य नहीं था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण हेतु पहली बैठक संसद भवन में 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी जिसमें 207 सदस्य शामिल हुए थे। भारत का संविधान हस्तलिखित है जिसे प्रेम बिहारी ने अंग्रेजी एवं हिंदी में विशेष शैली एवं तकनीक से लिखा है। मूल प्रति में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं जिसके प्रत्येक पृष्ठ में देश के प्रसिद्ध चित्रकारों के बनाए हुए आकर्षक मोनोहारी पारम्परिक चित्र दृष्ट्य हैं।

हमारा संविधान लोक के लिए स्वतंत्रता, न्याय,

समानता, बंधुत्व एवं सह-अस्तित्व का लक्ष्य लेकर चल रहा है जिसे प्राप्त करने का उपाय लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य रचना है। राजनीतिक न्याय के लिए एक व्यक्ति के एक वोट निश्चित है। उसका एक वोट सरकार के निर्माण में सहायक है और देश के विकास में भी। एक वोट का क्या महत्व है इसको हम प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की सरकार का 1 वोट से गिर जाने से समझ सकते हैं। लोक की समृद्धि में ही राष्ट्र की समृद्धि है और समृद्धि के लिए आवश्यक है परस्पर प्रेम, सद्भाव, माधुर्य; जहां गैर बराबरी के लिए कोई जगह न हो, जहां एक धरातल पर अवस्थित हो सभी अपनी पात्रता, क्षमता एवं रुचि-सुविधानुसार कार्य कर सकें। जहां मानव मानव में कोई भेदभाव की दीवार न हो। इसीलिए अस्पृश्यता एवं उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। लेकिन एक नागरिक की स्वतंत्रता एवं अधिकार दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता एवं अधिकार के उल्लंघन का निषेध करता है। हमारी स्वतंत्रता अन्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बन सकती। हम कल्याणकारी समाप्तमूलक समाज रखते हुए देश को संपूर्ण विश्व में प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, शांति, समृद्धि का ध्वजावहक सिद्ध कर सकने में यथा सामर्थ्य कटिबद्ध होकर कर्मरत होंगे, यही हम सबका शुभ संकल्प होगा।

अजावस के अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज में भारी रोष

परशुराम सेना का विरोध, कानूनी कार्रवाई की मांग की गई
इंदौर। अजावस संगठन के अध्यक्ष आईएमएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की महिलाओं को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद समाज में गहरा आक्रोह व्याप्त है। मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। इस क्रम में परशुराम सेना वंदेरा से जुड़े संदीप शर्मा ने एक वीडियो जारी कर समाज के विरोध को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा की टिप्पणी समाज का अपमान है, इसके खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि समाज कानूनी और सामाजिक रूप से इस मुद्दे पर मुखर रहेगा तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेगा। संदीप शर्मा ने यह भी कहा कि यदि इस प्रकरण में किसी सामाजिक कार्यकर्ता पर कानूनी कार्रवाई होती है तो उसका कानूनी खर्च परशुराम सेना द्वारा वहन किया जाएगा। समाज के वरिष्ठ लोगों का कहना है कि किसी भी समुदाय की महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी अस्वीकार्य है। ब्राह्मण समाज ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को जांच कर आवश्यक वैधानिक कदम उठाए जाएँ, ताकि भविष्य में कोई भी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति असम्मानजनक टिप्पणियाँ न कर सके। पूरे प्रकरण को लेकर शहर में चर्चा बनी हुई है और समाजजन शांति एवं कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं।

खंडवा रोड पर बस-बाइक मिड़त में दो किशोरों की दर्दनाक मौत

सिमरोल में फिर बड़ा हदसा, चालक बस छोड़कर फरार
इंदौर। सिमरोल थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक बार फिर तेज रफ्तार ने दो मासूम जिंदगियां निगल लीं। खंडवा रोड स्थित चोखी ढाणी के पास निर्माणाधीन पुल के करीब एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी,जिसमें दो किशोर विजय मावी (18) और रवी मावी (17) की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों शिव नगर गांव के रहने वाले थे और काम खत्म कर घर लौट रहे थे। गंभीर हालत में उन्हें एमवाय अस्पताल लाया गया,जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हदसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जल्द कर लिया है। सिमरोल थाना प्रभारी अमित भीमोर ने बताया कि प्राथमिक जांच में ओवरक्रेड के दौरान हुई टक्कर की आशंका जताई गई है। मृतक आपस में चचेरे भाई थे और मजदूरी का कार्य करते थे। पिछले कुछ महीनों में इंदौर में बसों की टक्कर से होने वाली दुर्घटनाओं में तेज बढ़ोतरी हुई है। 3 नवंबर को भेरूवाट में बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 31 अक्टूबर और 17 सितंबर को भी बसों की टक्कर में कई लोगों की जान जा चुकी है। 20 अगस्त को मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी की बस से हुए हदसे में दो लोगों की जान गई थी। लगातार हो रहे हदसों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

डिवाइडर में घुसी कार, जनहानि नहीं

इंदौर। हदसे से बचने पुलिस लगातार वाहन चालकों को समझाइश दे रही है। इसके बावजूद दो और चार पहिया वाहन चालक अनियंत्रित गति से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे वे कई बार हदसे के शिकार भी हो जाते हैं। सोमवार शाम सवा छह बजे के लगभग कार क्रमांक एएमपी-09-सीबी-1766 का चालक सत्य साई चौहान्हे से देवासनाका की ओर जा रहा है। कार की गति काफी तेज थी। बाइक सवार को बचाने के चक्र में वह गेटेल मोटर्स के सामने बीआटीएस के डिवाइडर में घुस गया, जिससे कार के अगले हिस्से को काफी नुकसान हुआ है। हदसे में चालक को मामूली चोट आई है।

कार का कांच फोड़कर गहने चुराए

इंदौर। किला मैदान गुट्केशर मंदिर के बाहर खड़ी कार से अज्ञात बदमाश ने कांच फोड़कर लाखों के गहने और नकदी चुरा लिए। पीड़ित परिवार खरगोन से यहां शादी समारोह में शामिल होने आया था। पुलिस ने मामले को जांच शुरू कर दी है। सत्र बाजार पुलिस के अनुसार, जब परिवार समारोह में शामिल होकर एक घंटे बाद लौटा तो उन्होंने देखा कि कार का आगे का कांच टूटा हुआ था। आगे की सीट पर रखे बैग की जांच करने पर पता चला कि उसमें रखा 45 हजार रुपए और सोने की ज्वेलरी गायब थी।

बैतूल में नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन

वरिष्ठ नेताओं ने गांव-गांव संगठन मजबूत करने का दिया संदेश

बैतूल। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय गंज में हुए युवा कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और जिलाध्यक्ष नित्य ढाणा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हर गांव में 20-20 कार्यकर्ताओं की टीम बनाने के निर्देश दिए।

पूर्व विधायक धरमू सिंह सरिसमा और ब्रह्मा भलाबी ने युवाओं को आगामी चुनावों के लिए अभी से कमर कसने और जिले की सशक्त आवाज बनकर काम करने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष संजय सरदार यादव ने बताया कि जिले में पचास हजार से अधिक युवा कांग्रेस सदस्य बनाए गए हैं और सभी को युवा कांग्रेस चुनाव के माध्यम से सौंपी गई जिम्मेदारिता का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। सम्मेलन में सभी ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही तथा नित्य ढाणा ने 27 नवंबर को भोपाल में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव किया जाएगा(जिसमें जिले के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप



प्रज्वलन से हुई। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी युवा निर्वाचित होकर आए हैं और अब जिले के प्रत्येक गांव में कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना उनका पहला दायित्व है।

जिलाध्यक्ष नित्य ढाणा ने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि युवा कांग्रेस पार्टी की मजबूती की रीढ़ है और युवाओं के मुंहों पर पूरे जिले में सक्रियता से काम किया जाना चाहिए।

वहीं पूर्व विधायक ब्रह्मा भलाबी ने कहा

कि युवा कांग्रेस से ही निकलकर कई बड़े नेता पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, इसलिए सभी पदाधिकारी बैतूल जिले की सशक्त आवाज बनकर कार्य करें। कार्यक्रम में ब्रजभूषण पांडे, समीर खान, अनुराग मिश्रा, नितिन गाडगे, मनोज आर्य, लवलेश राठौर, पुष्पा पेंदाम, जगदीश गोचरे सहित सभी युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पार्टी गणछे से स्वागत किया और अंत में राष्ट्रगान हुआ।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट कार्या करने वाले बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजरों का किया सम्मान

बैतूल। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान जिले में डिजिटाइजेशन कार्य में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को शाल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने आमला, मुलताई, घोड़ाडोंगरी और भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजरों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मतदाता सूची की सराहना करते हुए कहा कि मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी, लोकतांत्रिक प्रणाली उतनी ही मजबूत होगी। बीएलओ ही वो कड़ी हैं जो घरघुंघर जाकर मतदाताओं की सही जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सटीक रूप में दर्ज करते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण बड़ी जिम्मेदारी होती है। पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना, गलत प्रविष्टियों को सुधारना और जो अपात्र हैं उन्हें हटाना ये काम बेहद संवेदनशील हैं। आप सभी ने समय पर और गुणवत्तापूर्ण काम कर सराहनीय कार्य किया है।

इन बीएलओ ने किया शत प्रतिशत



डिजिटाइजेशन.- बैतूल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक -131 के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 150 के बीएलओ बारीकराव सरियाय प्राथमिक शिक्षक ने 558 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया है। इसी प्रकार मतदान केंद्र क्र 170 के बीएलओ सुनिल पदाम शिक्षक ने 519 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन तथा मतदान केंद्र 221 के बीएलओ दिनेश माथनकर शिक्षक ने 529 मतदाताओं का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया है। घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-132 के मतदान केंद्र 9 के बीएलओ सुरे सिंह काजले प्राथमिक शिक्षक ने 163 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन, मतदान केंद्र 87 की बीएलओ श्रीमती पूजा मंडल माध्यमिक

शिक्षक ने 506 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया। इसी प्रकार भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र क्र- 133 के मतदान केंद्र 37 की बीएलओ श्रीमती सकुन उड्डेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने 121 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य तथा मतदान केंद्र 318 के बीएलओ पांडुरंग अमरघड़े प्राथमिक शिक्षक, सहायक शंकर चरपे शिक्षक व ग्राम कोटवार राम भाऊ ने 327 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया है।

इन बीएलओ सुपरवाइजरों ने किया शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन.-आमला विधानसभा क्षेत्र क्र-130 के बीएलओ सुपरवाइजर पुरुषोत्तम यादव उच्च माध्यमिक शिक्षक, रामप्रसाद पाल उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा अनिल बिंझाड़े उच्च माध्यमिक शिक्षक ने अपने प्रभार के 10 मतदान केंद्रों पर शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया

है, जो मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण करने वाली विधानसभा है। इसी प्रकार मुलताई विधानसभा क्षेत्र 129 के बीएलओ सुपरवाइजर माधव कुमार बिसदे उच्च माध्यमिक शिक्षक ने 99.27 प्रतिशत तथा बीएलओ सुपरवाइजर हेमन्त कुमार पाटील उच्च माध्यमिक शिक्षक ने 98.91 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है।

11 लाख 5 हजार 278 गणना प्रप्र मतदाताओं ने किए जमा-बैतूल जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अन्तर्गत वृ्ध लेवल ऑफिसर द्वारा भरे हुए गणना पत्रों को बीएलओ एप के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। गणना पत्रक के कार्य की प्रगति की सतत समीक्षा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा की जा रही है। जिसके फलस्वरूप जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा बीएलओ एप के माध्यम से गणना पत्रक ऑनलाइन डिजिटाइजेशन कार्य प्रगति से किया जा रहा है। अब तक करीब 11 लाख 5 हजार 278 गणना प्रपत्र मतदाताओं द्वारा भरकर बीएलओ को जमा करा दिए हैं।

सुयोग कॉलोनी में कुतों का आतंक घर के बाहर खड़े युवक को काटा, नपा सीएमओ को सौंपा जाएगा

बैतूल। सुयोग कॉलोनी विकास नगर बैतूल में पालतू और आवारा कुतों के बढ़ते खतरे को लेकर आवेदक राजेश यादव ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जापान सौंपा है। राजेश यादव ने अपने जापान में लिखा है कि 22 नवंबर को उनके घर के ठीक सामने एक कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और उनके हाथ में काट लिया। कुत्ते के गले में चैन भी थी, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि वह कुत्ता किसी का पालतू था या फिर आवारा घूम रहा था। राजेश यादव ने सीएमओ से निवेदन करते हुए कहा है कि सुयोग कॉलोनी में लगातार बढ़ रहे कुतों के आतंक से कॉलोनी के लोग दहशत में हैं और कभी भी किसी बड़ी घटना की संभावना बनी रहती है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से आग्रह किया है कि क्षेत्र में घूम रहे पालतू एवं आवारा कुतों की तत्काल पकड़ धकड़ कराई जाए, ताकि सुयोग कॉलोनी में सुरक्षित माहौल बन सके।

वैकल्पिक राजनीति पर उड़ीसा में हुआ मू्थन, देश भर से जुटे पदाधिकारी

बैतूल। समाजवादी जनपरिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन उड़ीसा के टीटलागढ़ में हुआ। समाजवादी जनपरिषद एक राजनीतिक दल होकर पार्टी के विधान अनुसार हर 2 वर्ष में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी किया जाता है। यह सम्मेलन 22-23 नवम्बर को उड़ीसा राज्य के बलांगीर जिला अंतर्गत आने वाले टीटलागढ़ में आयोजित किया गया।

आठनेर में शुरू हुई आधुनिक एसओडीईएस डिजिटल लाइब्रेरी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और केंद्रीय राज्यमंत्री ने किया शुभारंभ, ग्रामीण अंचल में रहने वाले विद्यार्थियों हेतु खुला ज्ञान का नया द्वार
बैतूल। आठनेर में ग्रामीण छात्रों और युवाओं हेतु बहुप्रतीक्षित एसओडीईएस डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला पत्थर रखी गई।



उपलब्ध हो रही है और यह लाइब्रेरी युवाओं हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। केंद्रीय राज्यमंत्री डीडी उड्डे ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञानवर्धन का सशक्त माध्यम बनेगी और अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ लेना चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोवर्धन राने, मनोज जगताप, सुरज राठौर, पूर्व अध्यक्ष अजय फोरोफोड़े, पूर्व पंचद बटी अडलक, भवानी कपूरसेर सेंटर आठनेर के छात्र-छात्राएं और नगर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व संचालक और पूर्व पार्षद डॉ. प्रतिभा सतीश ठाकरे ने डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता पर जोर देते कहा कि हमारा प्रयास है कि ऐसी सुविधा दी जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़े शहरों जैसी डिजिटल शिक्षा उनके गांव में ही मिल सकेगी और यह पहले युवाओं के भविष्य निर्माण में मौल का पथर साबित होगी। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित अध्ययन ही आने वाले समय की वास्तविकता है।

कार्यक्रम के समापन पर भवानी कपूरसेर सेंटर के संचालक सतीश ठाकरे ने सभी अतिथियों एवं नगरवासियों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि लाइब्रेरी को सफल बनाना पूरे आठनेर की सामूहिक जिम्मेदारी है और यही प्रयास क्षेत्र के विद्यार्थियों को नई दिशा प्रदान करेगा।





नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री



सशक्त किसान समृद्ध मध्यप्रदेश

अन्नदाता को एमएसपी की गारंटी सोयाबीन भावांतर योजना

अंतर्गत

1.34 लाख
किसानों को
₹249 करोड़
की राशि का अंतरण



इनगोरिया - देपालपुर मार्ग
निर्माण का भूमिपूजन

₹264 करोड़ के
विकास कार्यों का
भूमिपूजन एवं लोकार्पण



अब तक

4.39 लाख किसानों द्वारा
7.85 लाख मीट्रिक टन
सोयाबीन का विक्रय

मुख्यमंत्री

डॉ. मोहन यादव

द्वारा

26 नवम्बर, 2025

अपराह्न 1:00 बजे
गौतमपुरा, जिला इंदौर

D-11150/25

सीधा प्रसारण

@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh

@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP

jansamparkMP

आकल्पन: म.प्र. माध्यम/2025